



भारत के कोयला क्षेत्र की हरति पहल

प्रलम्बिस् के लयि:

शुद्ध शून्य उत्सर्जन, राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC), पेरसि समझौता, गरीनहाउस गैस उत्सर्जन, हाइब्रिडि और इलेक्ट्रिकि वाहन योजना, वाहन स्करैपगि नीति, वैश्वकि EV30@30 अभयान, UNFCCC COP26, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हाइड्रोजन ऊर्जा मशिन, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) ।

मेन्स के लयि:

भारत के कोयला क्षेत्र की हरति पहल, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC) को प्राप्त करने के लयि भारत द्वारा उठाए गए आवश्यक कदम ।

चर्चा में क्यों?

कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनयिों के लयि वर्ष 2022-23 के दौरान [कोयला क्षेत्रों](#) में और इसके आसपास के क्षेत्रों में 2400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को हरति आवरण (गरीन कवर) के तहत लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य नरिधारति कयिा है ।

- वर्ष 2022-23 में 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है ।

हरति पहल

- चहिनति क्षेत्र:**
 - चहिनति क्षेत्रों में कोयला कंपनयिों के पुनः प्राप्त खनन क्षेत्र और राज्य सरकार की एजेंसयिों द्वारा उपलब्ध कराये गये पट्टेदार से बाहर के क्षेत्र शामिल हैं ।
- उपलब्धि:**
 - अब तक कोयला खनन क्षेत्रों में हरति अभयान व्यापक है और 15 अगस्त, 2022 तक लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि को ब्लॉक पौधरोपण, एवेन्यू पौधरोपण, घास के मैदान नरिमाण, बाँस वृक्षारोपण और उच्च तकनीक खेती के माध्यम से कवर कयिा जा चुका है ।
 - उदाहरण: तमलिनाडु में NLCIL के खदान-1 भूमि-सुधार क्षेत्र में धान के खेत और नारयिल का बागान एवं मध्य प्रदेश के सगिरौली में NCL के नगिाही क्षेत्र में बायो-रकिलेमेशन (नमिनीकृत मृदा को उत्पादक भूमि में परिवर्तित करना) ।
- महत्त्व:**
 - वनरोपण मानवजनति गतिविधियिों से क्षतगिरसत भूमि को फरि से उपयुक्त बनाने का एक प्रामाणिक तरीका है और यह खनन कार्य समाप्त हो चुके क्षेत्र के संतोषजनक पुनर्वास को प्राप्त करने के लयि आवश्यक है ।
 - कोयला क्षेत्र की हरति पहल वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बलियिन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बराबर अतिरिक्त कार्बन संचय करने के लयि भारत की [राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#) की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है ।
 - भारत ने हाल ही में अपने [NDCs में संशोधन](#) कयिा है ।
 - हरति पहल कोयला खनन के असर को कम करने में मदद करता है, मृदा के कटाव को रोकता है, जलवायु को स्थिर करता है, वन्य जीवन को संरक्षति करता है और वायु एवं जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है ।
 - वैश्वकि स्तर पर, यह कार्बन की मात्रा में कमी लाने के माध्यम से [जलवायु परिवर्तन](#) की गति को कम करता है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होता है ।
 - भारतीय कोयला उद्योग का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के वभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लयि कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करते हुए स्थानीय नवासयिों के लयि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है ।

भारत के संशोधति NDC

■ परचिय:

○ उत्सर्जन तीव्रता:

- भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से **सकल घरेलू उत्पाद (GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन)** की **उत्सर्जन तीव्रता** में कम-से-कम 45% की कमी करने के लिये प्रतबिद्ध है।
- मौजूदा लक्ष्य के तहत **33% – 35% की कमी करना था।**

○ वदियुत उत्पादन:

- भारत यह सुनिश्चिती करने का भी प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2030 में स्थापित वदियुत उत्पादन क्षमता **कम से कम 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित हो।**
 - यह वर्तमान के 40% लक्ष्य से अधिक है।

■ अन्य NDC:

- वर्ष 2030 तक **गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना।**
- वर्ष 2030 तक **कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना।**
- वर्ष 2070 तक **शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना।**

INDIA'S CLIMATE TARGETS: EXISTING AND NEW

Target (for 2030)	Existing: First NDC (2015)	New: Updated NDC (2022)	Progress
Emission intensity reduction	33-35 per cent from 2005 levels	45 per cent from 2005 levels	24 per cent reduction achieved in 2016 itself. Estimated to have reached 30 per cent
Share of non-fossil fuels in installed electricity capacity	40 per cent	50 per cent	41.5 per cent achieved by the end of June this year
Carbon sink	Creation of 2.5 to 3 billion tonnes of additional sink through afforestation	Same as earlier	Not clear.

जलवायु परिवर्तन की दशा में भारत की पहल:

■ परविहन क्षेत्र में सुधार:

- भारत तीव्र अनुकूलन और **हाइड्रडि और इलेक्ट्रिक वाहन योजना** के निर्माण के साथ अपने **ई-मोबिलिटी संक्रमण** में तीव्रता ला रहा है।
- पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिये **सर्वेच्छिक वाहन सकरैपि नीति** मौजूदा योजनाओं की पूरक है।

■ इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत उन गनि-चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक **'EV30@30 अभियान'** का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बकिरी में इलेक्ट्रिक वाहनों की हसिसेदारी को कम-से-कम 30% करना है।
- ग्लासगो में **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फरेमवरक कनवेंशन (United Nations Climate Change Framework Convention-UNFCCC) CoP26** में जलवायु परिवर्तन से उपाय के लिये पाँच तत्त्वों **"पंचामृत"** की अवधारणा को प्रस्तुत करना भारत के लिये इन्ही कदमों में से एक है।

■ सरकारी योजनाओं की भूमिका:

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** द्वारा 88 मिलियन परिवारों को **कोयला आधारित खाना पकाने के ईंधन से एलपीजी कनेक्शन** में स्थानांतरित किया गया है।

■ नमिन-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका:

- भारत में सार्वजनिक और नजी क्षेत्र पहले से ही जलवायु चुनौती को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ग्राहकों और नविशकों की बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ **नियामक और प्रकटीकरण आवश्यकताओं** को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

■ **हाइड्रोजन ऊर्जा मशिन:**

- हरित ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान देना।

■ **प्रदर्शन, उपलब्धि और वयापार (Perform, Achieve and Trade-PAT):**

- PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की **ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु** लागत प्रभावीता बढ़ाने के लिये एक **बाज़ार आधारित तंत्र** है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2017 में लागू हुआ था।
2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिकी स्तरों से 2°C या 1.5°C से अधिक न हो।
3. विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने हेतु वर्ष 2020 से सालाना 1000 अरब डॉलर की मदद के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

व्याख्या:

- पेरिस समझौते को दिसंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में पार्टियों के सम्मेलन (COP) द्वारा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के माध्यम से अपनाया गया था।
- समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिकी स्तरों से 2°C या 1.5°C से अधिक न हो। **अतः कथन 2 सही है।**
- पेरिस समझौता 4 नवंबर, 2016 को लागू हुआ, जिसमें वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अनुमानित 55% तक कम करने के लिये अभिसमय हेतु कम-से-कम 55 पार्टियों ने अनुसमर्थन, अनुमोदन या परगिरहण स्वीकृति प्रदान की थी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- इसके अतिरिक्त समझौते का उद्देश्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिये देशों की क्षमता को मज़बूत करना है।
- पेरिस समझौते के लिये सभी पक्षों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को मज़बूत करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी शामिल है कि सभी पक्ष अपने उत्सर्जन और उनके कार्यान्वयन प्रयासों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करें।
- समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि में सामूहिक प्रगति का आकलन करने और पार्टियों द्वारा आगे की व्यक्तिगत कार्रवाइयों को सूचित करने के लिये प्रत्येक 5 साल में एक वैश्विक समालोचना भी होगा।
- वर्ष 2010 में कानकून समझौतों के माध्यम से विकसित देशों को विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध किया।
- इसके अलावा वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वर्ष 2025 से पहले पेरिस समझौते के लिये पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत पार्टियों का सम्मेलन प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करेगा। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)